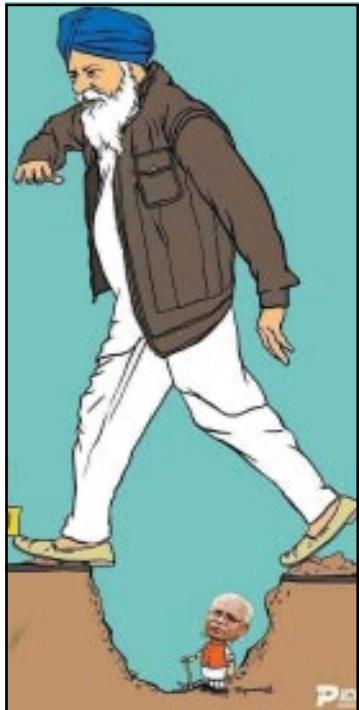


व्यंग्य मोदी जी, आप किसानों के आगे झुक रहे हो!



वैसे भी अभी चार-छह दिन पहले तो आपने कहा था न कि ये तीन कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों को भड़काया जा रहा है और अब आपकी ही सरकार किसानों की बात कुछ-कुछ मानती हुई-सी लग रही है। यह क्या हो रहा है मोदी जी! आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इमेज को कहीं आपके ही लोग धक्का तो नहीं पहुँचा रहे हैं! लेकिन आपकी इमेज अब केवल आपकी इमेज नहीं है। यह आपके भक्तों की इमेज भी है। इसे धूल में मिलाने की इजाजत आपको भी नहीं दी जा सकती!

अरे आप तो संविधान के आगे नहीं झुकें, कानून के आगे नहीं झुकें। संसद के आगे नहीं झुकें आंदोलनों के आगे नहीं झुकें, अद्वालत के आगे नहीं झुकें और जो बच गए, जो नहीं झुकें, जो झुक नहीं सके, उनके लिए आपने जेल में इतना अच्छा इंतजाम करवा दिया है कि एकदम मौत के करीब जब तक कोई पहुँच न जाए, तब तक आप उनको अस्पताल तक भी पहुँचने नहीं देते! आप तो ऐसे अद्वृत कलाकार हो कि जिस समुदाय के खिलाफ दंगा भड़काया, उसीके लोगों को निशाने पर ले लेते हो। आप तो ऐसे महामना हो कि सीएए और एन आर सी के खिलाफ आंदोलन करनेवालों को 'देशद्रोही' बना देते हो। आप तो ऐसे 'देशभक्त' हो कि आपने अपने लोगों, अपने गोदी चैनलों के जरिए इन किसानों को खालिस्तानी, नक्सलवादी बता देते हों और अब आप इन्हें के आगे झुकते हुए लगें और वह भी इसलिए कि ये बहुत बड़ी तादाद में हैं और इन्होंने दिल्ली घेर रखी हैं और इन्हें देश-विदेश से समर्थन मिल रहा है। भक्त समझेंगे कि हिन्दू-हृदय सम्प्राट खालिस्तानियों-नक्सलियों से डर गया। कायर मत बनो। प्रेस कांफ्रेंस करने से डरो मगर किसानों को ठीक करने से मत डरो!

आप अपने नाम पर इस तरह बबूना नहीं लगने दे सकते! ऐसा हुआ तो फिर लोग मोदी जी को मोदी जी नहीं मानेंगे! छह साल बाद अब आप झुकने लगे हैं, बताइए आपकी यह इमेज बन गई तो इसका मैसेज कितना बुरा जाएगा! फिर तो जो देखो, वही शेर हो जाएगा, आप पर सवारी गाँठने लगेगा! ब्रांड मोदी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अपने को बाबा रामदेव मत बनने दो।

हे भगवान, क्या हो गया है इस 'हिन्दू-हृदय सम्प्राट' को कहीं उसका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो रहा है? लेकिन मौदी जी का तो हृदय ही नहीं है तो उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है! बिना हृदय के हृदय परिवर्तन? ऐसा तो कभी हुआ नहीं मानव इतिहास में! हिन्दी कहानी में भी नहीं हुआ!

मोदीजी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप होशियार हो तो ये किसान आपसे डबल होशियार हैं। जानते हैं आपको कि आप बहुत ऊँची रकम हो, तो वे भी काफी तैयारी से आए हैं। आप तो इमेज बनाते हो कि किसान भोले भाले होते हैं, उन्हें कोई भी भड़का सकता है मगर लगता है, ऐसा नहीं है। ये जानते हैं कि आपसे लड़ाई लंबी भी चल सकती है, इसलिए छह महीने का राशनपानी साथ लेकर आए हैं इनके दिमाग साफ हैं। आपको अपना एजेंडा मालूम है तो इनको भी अपना एजेंडा मालूम है ये अफसरों-मंत्रियों के झाँसे में आनेवाले नहीं इसलिए जरा सावधानी से चलिओ वरना ये आपकी सारी कार्ति का हरण कर लेंगे लगता है, इस बार शेर को सवा शेर मिल गया है। मैंने बता दिया साफ-साफ, बाकी आप जानो। हिन्दू राष्ट्रवाद की रक्षा की जिम्मेदारी आपने ली है, मैंने नहीं!

मझे आश्र्य है कि मोदी जी आपने इन्हें लड़ाने का खेल अभी तक शुरू क्यों नहीं किया! आपने हिन्दूओं-मसलमानों को बढ़िया से लड़ा दिया, पिछड़ों-पिछड़ों और दलितों-दलितों को भी लड़ा दिया किसानों को भी जल्दी से लड़ा दो न, आपस में टटा मुकाब्ला। इनकी एकता आपकी कुसीं, आपकी पार्टी के लिए धातक है यानी आपकी भाषा में देश के लिए धातक है देश के सामने खतरा देखकर भी चुप रहे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, मोदीजी! किसानों को चान मत समझो, पाकिस्तान समझो! चुप मत रहो, इशारे में बातें मत करो और चलाओ अंगे जोंवाली चाल-बाँटो और राज करो। जय हिन्द, जय भारत विंदेमातरम! भारत माता की जय। मोदी-मोदी।

श्रम किसान आन्दोलन के समय ट्रेड यूनियनों की अनुपस्थिति

सतीश कुमार

बेशक देश भर की तमाम ट्रेड यूनियनों (बीएमएस को छोड़कर) ने किसान आन्दोलन का समर्थन किया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर सहयोग करने की बात कही है। 9 दिसंबर के भारत बंद में साथ रह कर कारखाने बंद करने को कहा है, परन्तु धरातल पर कहीं कुछ नजर नहीं आता। दरअसल ट्रेड यूनियनों के नाम पर केन्द्रीय 'मठाधीशों' ने समर्थन एवं बंद की घोषणा तो कर परन्तु इस घोषणा को अमली जामा पहनाने वाला काढ़ता तो धरातल से गायब है, किसी एक का नहीं बल्कि सभी फ्रेडरेशनों का हाल लगभग एक जैसा है। फ्रीडावाद, गुड़ानाव तथा कुछ और जगहों पर सीट वालों ने जस्तर कुछ रस्म अदायगी करके सड़कों पर हाजरी दर्ज कराई है, परन्तु ठोस एवं प्रभावी वे भी कुछ खास नहीं कर पाये। लाखों मजदूरों के शहर में मात्र 50-100 लोगों की रैली-प्रदर्शन क्या मायने रखती है?

सीट ने चले रस्म अदायगी तो की बाकी इन्टक, एटक, एचएमएस आदि की तो कहीं रस्म अदायगी भी नजर नहीं आई। हां एक छोटा सा नवजात संगठन इंकलाबी मजदूर केन्द्र के लोग जरूर कुछ करते नजर आये। बेशक उनकी संख्या कम रहती है परन्तु वे जन विरोधी मुद्दों का संज्ञन लेकर सदैव ही प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं।

ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मुखिया जो अपने-अपने कार्यालयों से समर्थन एवं बंद का फ्रमान जारी करके निश्चित हो जाते हैं क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज देश के 75 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक मजदूर किसी भी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं रह गये हैं क्योंकि वे केजूअल हैं या ठेकेदारी में हैं या टेनी के नाम से अपनी मेहनत बेचने को मजबूर हैं। शेष बचे करीब 25 प्रतिशत भी केवल नामचारे को ही सदस्य रह गये हैं। उनके लिये यूनियन केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति यानी अच्छे बेतन, बढ़िया सेवा शर्तों के साथ सुरक्षित नौकरी की गारंटी के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके लिये ऐसा कोई भूल नहीं है कि जिसके द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ न मिलता हो, ऐसे में उन्हें क्या लेना किसानों के संघर्ष से? वे क्यों अपनी दिहाड़ी व उर्जा गंवाने लगे बिना मतलब के?

दरअसल इसके लिये मजदूर कतई दोषी नहीं हैं, कोई दोषी है तो मजदूर नेता जो मठाधीश बन कर यूनियनों पर कुंडली मारे बैठे हैं। मजदूर को ट्रेड यूनियन का दर्शन एवं राजनीति पढ़ाने तथा व्यापक मजदूर वर्ग के भाईंचारे के प्रति जागरूक करने की अपेक्षा अपने-अपने जिजी हित साधने में जुटे हैं, तरह-तरह के व्यापार करने में व्यस्त हैं। इसी के चलते मजदूरों के बीच उनकी इतनी साख और विश्वसनीयता भी नहीं बची है।



जो मजदूर उनके आहान पर एकजुट होकर खड़े हो जायें। 'बोये पेड बबूल के तो आम कहां से होए' वाली कहावत यहां पूरी तरह चरितर्थ होती है।

रेलवे इस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। मोदी राज से पूर्व इसमें 15 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। लाखों पद रिक्त होने व नई भर्तियां न होने के चलते करीब चार लाख पद घट गये हैं। शायद ही कोई ऐसी राष्ट्रीय फ्रेडरेशन हो जिसकी यूनियन सदस्यता इस उपक्रम में न हो। किसी जमाने में अपनी प्रभावशाली छवि रखने व लम्बी हड्डालों के जरिये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी रेलवे यूनियन भी आज मृत प्रायः है। आज के किसान आन्दोलन के पक्ष में जहां न केवल पूरे देश में बल्कि विदेशों तक में समर्थक सड़कों पर उत्तर आये हैं, रेलवे की किसी भी यूनियन ने जबान तक भी नहीं हिलाई, हाथ-पैर हिलाना तो दूर की बात है।

दरअसल रेलवे यूनियन किसी और के लिये क्या संघर्ष करेंगी वे तो अपनी ही दुर्शा पर रोने लायक नहीं बचे हैं। मोदी सरकार पूरी रेलवे को ही बेचने की तैयारी में जुटी है। इसके लिये जरूरी है कि कर्मचारियों की संख्या कम से कम करके इसे नये कार्पोरेट मालिकों को सौंपा जाए। कोई भी नया मालिक नहीं चाहता कि उसे उद्योग के साथ-साथ कर्मचारियों का बोझ भी ढोना पड़े। कार्पोरेट इन कर्मचारियों को बहुत महंगा, निकम्मा, हरामखोर व रिश्वतखोर मान कर चलता है। वह अपने हिसाब से अपनी पसंद के सस्ते से सस्ते कर्मचारी भर्ती करके रेलवे को चलाना चाहेगा। इसी की तैयारी में मोदी ने 50 प्रतिशत से अधिक ट्रेनें बंद कर छोड़ी हैं। जो बड़ी ट्रेनें चल भी रही हैं उनमें टिकट के दाम अनाप-शनाप बढ़ाये जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि कम ट्रेनों के चलाने से आय में जो कमी

आयेगी उसकी पूर्ति किसाये बढ़ा कर की जायेगी। यही कार्पोरेट मॉडल है।

कार्पोरेट मॉडल की सुविधाजनक सफलता एवं मुनाफाखोरी को सुनिश्चित करने के लिये मोदी ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है। इसमें सबसे ज्यादा काम आया कोरोना। कोरोना महामारी का भय दिखा कर दिल्ली-पलवल-मथुरा तक चलने वाली तमाम शटल एवं पैसेंजर ट्रेनें पहले तो अस्थाई रूप से बंद की गयी थी लेकिन अब वे स्थाई रूप से बंद कर दी गयी हैं। इन छोटी ट्रेनों से यात्रा करने वाले दैनिक यात्री, जो निम्न मध्य वर्ग के मेहनतकश होते हैं। इन यात्रियों की तरफ से भी कोई आवाज न उठने के चलते सरकार